

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3655

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन इकाइयां

3655. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में उर्वरक उत्पादन के लिए नए कारखाने स्थापित करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो वे कौन-से राज्य हैं जहां ये कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है और इनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने मौजूदा उर्वरक कंपनियों में उर्वरक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण के लिए उपाय किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो क्या प्रमुख पहल की गई हैं और ये उर्वरक उत्पादन में दक्षता और स्थिरता को किस प्रकार बढ़ाएंगी;
- (ड.) क्या सरकार ने देशभर में भवन निर्माण में जिप्सम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (च) यदि हां, तो शुरू किए गए विशिष्ट उपायों का व्यौरा क्या है और उन्हें निर्माण क्षेत्र में अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार से लागू किया जा रहा है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क और ख): सरकार ने प्रत्येक 12.7 एलएमटीपीए क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की स्थापना के लिए नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तालचेर (ओडिशा) इकाइयों और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी (बिहार) इकाई को पुनर्जीवित करने के अधिदेश दिए। रामागुंडम और गोरखपुर इकाइयों को क्रमशः दिनांक 22.03.2021 और 07.12.2021 को प्रचालित कर दिया गया है। इसके अलावा, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः दिनांक 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। तालचेर इकाई निष्पादन चरण में है।

(ग और घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन नए यूरिया संयंत्रों को बहुत कम ऊर्जा खपत, लगभग 5.0 जीकैल/एमटी के लिए तैयार की गई नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित किया गया है। इसके अलावा, नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के तहत, यूरिया इकाइयों को लक्ष्य ऊर्जा मानदंड (टीईएन) दिए गए थे। यूरिया इकाइयों से टीईएन प्राप्त करने की अपेक्षा थी जिसके लिए इकाइयों ने संयंत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकीय उन्नयन को अपनाया है। परिणामस्वरूप, अब तक 19 यूरिया इकाइयों ने टीईएन प्राप्त कर लिए हैं। एनयूपी-15 मानदंडों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा खपत वर्ष 2014-15 के दौरान 6.04 जीकैल/एमटी से बेहतर होकर वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 5.59 जीकैल/एमटी हो गई है।

(ड.): शून्य।

(च): उपरोक्त (ड) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।
